

के. चिन्नास्वामी रेड्डी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(बी.पी.सिन्हा, सी.जे., के., एन. वांचू और जे. सी. शाह, जे.जे.)

दोषमुक्ति-पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय की शक्ति- पुनः विचारण -पुलिस जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान की स्वीकार्यता - दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5), धारा 439- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), धारा 27.

अपीलकर्ता, जिस पर दूसरे के साथ मुकदमा चलाया गया था, को भारतीय दंड संहिता की धारा के 411 तहत दोषी ठहराया गया था जबकि दूसरे को संहिता की धारा 457 एवं 380 के तहत सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ता ने जांच के दौरान पुलिस को बताया था कि वह "वह स्थान दिखाएगा जहां उसने आभूषणों को छुपाया था" और उसके बाद बगीचे में गए और खुदाई करके आभूषणों से भरे दो बंडल निकले। दूसरा आरोपी व्यक्ति ने भी इसी तरह कहा था कि उसने किसी बड़ा साब को आभूषण दिया था, पुलिस पार्टी को बड़ा साब के पास ले गये और उससे आभूषण लौटाने को कहा, जो उसने लौटा दिया। अपील पर सत्र न्यायाधीश ने यह विचार किया कि अपीलकर्ता के बयान का वह भाग जहां उसने कहा कि उसने आभूषण छिपा दिये हैं, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थे, और किसी अन्य साक्ष्य का अभाव में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आभूषण का कब्जा सिद्ध हो चुका है। इसलिए, उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार था और उसे बरी कर दिया। उन्होंने दूसरे आरोपी व्यक्ति के संबंध में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया और उसको

बरी कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया गया और पुनः विचारण के लिए निर्देशित किया गया। यह पुनः विचारण आदेश के विरुद्ध था कि अपील का निर्देश दिया गया।

यह माना गया कि पुनरीक्षण में और निजी पार्टी के कहने पर यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था कि बरी करने के आदेश को खारिज कर दे, हालाँकि हो सकता है राज्य अपील नहीं करता। लेकिन ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल अपवाद स्वरूप ही किया जाना चाहिए ऐसे मामले, जहां प्रक्रिया में कोई स्पष्ट दोष हो या कानून की स्पष्ट त्रुटि के कारण न्याय की गंभीर असफलता हुई है। जब संहिता की धारा 439(4) उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने से रोकती है तो यह उचित नहीं है कि उच्च न्यायालय पुनः परीक्षण का आदेश देकर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करे। ऐसे मानदंड निर्धारित करना संभव नहीं है जिनके आधार पर ऐसे असाधारण मामलों पर निर्णय लिया जा सके। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उचित होगा जैसे कि (1) जहां ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से साक्ष्य को बंद कर दिया था, जिसको अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई, (2) जहां अपील अदालत ने विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए सबूतों को गलत तरीके से अस्वीकार्य ठहराया, (3) जहां भौतिक साक्ष्य को विचारण न्यायालय या अपीलीय अदालत द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, (4) जहां दोषमुक्ति अपराध के शमन पर आधारित थी जो कानून और उपरोक्त जैसे मामलों द्वारा अनुमत नहीं है।

डी. स्टीफंस बनाम नोसिबोला, [1951] एससीआर 284 और लोर्गेन्द्र- नाथ झा, बनाम श्री पोलाईलाल विश्वास, [1951] एससीआर 676, संदर्भित किए गए।

मौजूदा मामले में कोई संदेह नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता के संपूर्ण बयान के साथ-साथ अन्य अभियुक्तों के बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा, और सत्र न्यायाधीश ने उनमें से कुछ हिस्सों को छोड़ने में गलती की, और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से दोषमुक्ति को रद्द करने में न्यायोचित था।

पुलुकुरी कोटाय्या बनाम किंग एम्परर, (1946) एल.आर. 74 आई.ए. 65, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 6/1960.

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 403/1958 और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 337/1957 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 1 जुलाई, 1959 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से पी. राम रेड्डी।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए के आर चौधरी और पीडी मेनॉन।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए के आर चौधरी।

25 जुलाई 1962.

न्यायालय का फैसला वांचू, जे. द्वारा सुनाया गया।

यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत कुरनूल के सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया था। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति हुसैन साहब पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 457

और 380 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह था कि 20 अप्रैल, 1957 की रात को दुदिया में रामय्या के घर में चोरी हो गई थी। रामय्या और उनकी पत्नी बाहर सो रहे थे और सुबह जागने पर उन्होंने पाया कि घर में चोरी हो गई थी और बहुमूल्य संपत्ति चोरी हो गई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और जांच के दौरान पुलिस ने अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पर 17 गहने बरामद किए। दूसरे आरोपी ने भी जानकारी दी थी जिसके आधार पर चोरी का एक और आभूषण बरामद कर लिया गया। सबूतों पर विचार करने के बाद सहायक सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दूसरे आरोपी ने वास्तव में घर में चोरी की थी और रामय्या के घर से गहने ले लिए थे और उस संपत्ति में से 17 गहने अपीलकर्ता को सौंप दिए थे। वह इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि अपीलकर्ता की निशादेही से बरामद किए गए सत्रह आभूषण उसके कब्जे में थे और इसलिए उसने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत दोषी पाया। अपीलकर्ता और अन्य आरोपी सत्र न्यायाधीश के पास अपील में गए। सत्र न्यायाधीश ने माना कि यह साबित नहीं हुआ कि वो सत्रह आभूषण, जो अपीलकर्ता के कहने पर बगीचे से बरामद किए गए थे, वो उसके कब्जे में थे। इस संबंध में अपीलकर्ता का कथन था कि "वह वह स्थान दिखाएगा जहां उसने उन्हें (आभूषणों को) छिपाया था।" इसके बाद वह बगीचे में गया और वहां से सत्रह आभूषणों से भरी दो गठरियां खोदकर निकालीं। सत्र न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता के कहने पर बगीचे से आभूषणों की बरामदगी साबित हुई; लेकिन उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के बयान का वह हिस्सा जहां उसने कहा था कि उसने गहने छिपाए थे, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, उन्होंने यह मान कि चूंकि आभूषण ऐसी जगह से बरामद किए गए थे जो सभी और विविध लोगों के लिए पहुंच योग्य था और यह दिखाने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता ने उन्हें छिपाया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आभूषण अपीलकर्ता के कब्जे में थे। इसलिए उन्होंने

अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया और उसे बरी करने का आदेश दिया। उन्होंने अन्य आरोपी को भी बरी कर दिया जिनकी निशानदेही पर चोरी के आभूषणों में से एक बरामद किया गया था। इस अभियुक्त ने कहा था कि उसने गहने बड़ा साब (पीडब्लू 5) को दिए थे और पुलिस दल को बड़ा साब के पास ले गया और उससे गहने वापस करने के लिए कहा, जो बड़ा सब ने किया। हालाँकि, सत्र न्यायाधीश ने अन्य आरोपी के खिलाफ सबूतों पर विचार करने पर सोचा कि उसके खिलाफ मामला भी संदिग्ध था और उसे बरी करने का आदेश दिया, हालाँकि उन्होंने रामय्या को गहने वापस करने का आदेश दिया। इसके बाद रामय्या द्वारा अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया गया। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की अनुमति दी है और निर्देश दिया है कि मामला सत्र न्यायाधीश के पास वापस जाना चाहिए ताकि आरोपियों पर उन आरोपों पर फिर से मुकदमा चलाया जा सके जिनके तहत उन पर पिछली बार मुकदमा चलाया गया था। पुनः सुनवाई का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि केवल चिन्नास्वामी रेड्डी ने अपील की है जबकि अन्य आरोपी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है।

हमारे समक्ष अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि यह एक निजी पक्ष द्वारा किया गया पुनरीक्षण था। इस मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी जो निजी पक्ष के कहने पर उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने को उचित ठहराती। इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (4) विशेष रूप से उच्च न्यायालय को बरी करने के फैसले को दोषसिद्धि में बदलने से रोकती है और उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि पुनः सुनवाई के अप्रत्यक्ष तरीके से उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय को अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का निर्देश दिया है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दोषमुक्ति के निष्कर्ष

को दोषसिद्धि में परिवर्तित कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं किया गया है और सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है।

दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में हस्तक्षेप करने के मामले में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा पर इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर विचार किया गया है। डी, स्टीफेंस बनाम नोसिबोला (1951- एससीआर 284) में इस न्यायालय ने कहा-

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का हल्के ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जब इसे एक निजी शिकायतकर्ता द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ लागू किया जाता है, जिसके खिलाफ सरकार के पास 417 के तहत अपील का अधिकार है। इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में किया जा सकता है जहां सार्वजनिक न्याय के हितों के लिए स्पष्ट अवैधता के सुधार या न्याय की घोर विफलता की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्राधिकार को साधारणतया केवल इसलिए लागू या उपयोग नहीं किया जाता है कि निचली अदालत ने कानून के बारे में गलत दृष्टिकोण अपनाया है या रिकॉर्ड पर सबूतों को गलत तरीके से समझा है।"

फिर से, लोर्गेद्रनाथ झा बनाम श्री पोलाईलाल बिस्वास (1) में, इस न्यायालय ने कहा-

"यद्यपि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 की उप-धारा (1) उच्च न्यायालय को धारा 423 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी भी अधिकार का अपने विवेक से प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

द्वारा अपील की अदालत पर, फिर भी उप-धारा (4) विशेष रूप से "बरी के फैसले को दोषसिद्धि में बदलने" की शक्ति को इससे बाहर रखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ किसी निजी पक्षकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका से निपटने में, कानून के किसी बिंदु पर किसी भी त्रुटि के अभाव में उच्च न्यायालय सबूतों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और उन तथ्यों के निष्कर्षों को उलट सकता है जिन पर बरी करने का आदेश आधारित था, बशर्ते वह पुनः मुकदमा चलाने का आदेश देकर आरोपी को दोषी ठहराने और उस पर सज़ा पारित करने से बचे।"

ये दो मामले स्पष्ट रूप से पुनरीक्षण में बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करते हैं; विशेष रूप से, लोर्गेद्रनाथ झा का मामला (1951- एससीआर 676) इस बात पर जोर देता है कि धारा 439 (4) के प्रावधानों के मद्देनजर बरी करने के फैसले को दोषसिद्धि में परिवर्तित करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है, और यह कि उच्च न्यायालय पुनः सुनवाई का आदेश देकर अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा नहीं कर सकता है। उस मामले में क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों के अभिमूल्यन के आधार पर तथ्यों के शुद्ध निष्कर्षों को उलट दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराए बिना केवल उन पर दोबारा मुकदमा चलाने का निर्देश देकर उप-धारा का (4) अनुपालन किया गया, और चेतावनी दी कि मामले की दोबारा सुनवाई करने वाली अदालत को उच्च न्यायालय के फैसले में निहित राय की किसी भी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस संबंध में इस न्यायालय ने पाया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पासा उस मामले के अपीलकर्ताओं के खिलाफ था और मामले से निपटने वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के लिए फैसले में व्यक्त किए गए

मजबूत विचारों को पूरी तरह से अलग रखना मुश्किल साबित हो सकता है, जहां तक अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता और सामान्य तौर पर मामले की परिस्थितियाँ का सवाल है।

यह सच है कि उच्च न्यायालय निजी पक्षों के कहने पर भी बरी करने के आदेश को रद्द कर सकता है, हालांकि राज्य ने अपील करना उचित नहीं समझा होगा; लेकिन हमारी राय में इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए, जब प्रक्रिया में कोई स्पष्ट दोष हो या कानून के किसी बिंदु पर कोई स्पष्ट त्रुटि हो और परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता हुई हो। धारा 439 की उपधारा (4) उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने से रोकता है और यह उच्च न्यायालय को यह देखने के लिए और अधिक उत्तरदायी बनाता है कि वह पुनः सुनवाई का आदेश देने की अप्रत्यक्ष विधि द्वारा दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं करे, जब यह स्वयं दोषमुक्ति के निष्कर्ष को सीधे तौर पर दोषसिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है। यह पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के निष्कर्ष को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर सीमाएं लगाता है और केवल असाधारण मामलों में ही इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे असाधारण मामलों को निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना संभव नहीं है जो सभी आकस्मिकताओं को कवर करेगा। हालाँकि, हम इस प्रकार के कुछ मामलों का संकेत दे सकते हैं, जो हमारी राय में पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय को उचित ठहराएगा। ये मामले निम्न तरह से हो सकते हैं: जहां ट्रायल कोर्ट के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आरोपी को बरी कर दिया है, या जहां ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उन सबूतों के लिए माना कर दिया है, जो अभियोजन पक्ष पेश करना चाहता था, या जहां अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा

स्वीकार किए गए साक्ष्यों को गलत तरीके से अस्वीकार्य माना लिया है, या जहां ट्रायल कोर्ट या अपील कोर्ट द्वारा तात्विक साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया गया है, या जहां बरी करना अपराध के शमन पर आधारित है, जो कानून के तहत अमान्य है। ये और समान प्रकृति के अन्य मामले उचित रूप से असाधारण प्रकृति के मामले माने जा सकते हैं, जहां उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है; और ऐसे मामले में यह स्पष्ट है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय अप्रत्यक्ष रूप से वह कर रहा था जो वह धारा 439 (4) के प्रावधानों के मद्देनजर सीधे नहीं कर सकता था। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या इस मामले में बरी करने के आदेश को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को इन सिद्धांतों पर बरकरार रखा जा सकता है।

उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि जहां तक अपीलकर्ता के खिलाफ मामले का संबंध है, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर बहुत विस्तार से विचार किया है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को सबूतों पर इतने विस्तार से विचार नहीं करना चाहिए था जब वह दोबारा सुनवाई का आदेश देने जा रहा था, क्योंकि सबूतों पर इतना विस्तृत विचार, जैसा कि लोर्गेद्रनाथ के मामले में बताया गया है (1951-एससीआर 676) पास अपीलकर्ता के खिलाफ करने जैसा है, जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए जाएगा। यदि मामला यहीं तक सीमित रहता, तो हमें उच्च न्यायालय के दोबारा सुनवाई के आदेश को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती; लेकिन इस मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसका उच्च न्यायालय ने सरसरी तौर पर उल्लेख किया है, जो, हमारी राय में, उच्च न्यायालय को इस मामले में दोषमुक्ति को रद्द करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त था। तब सबूतों पर उस विस्तार से विचार करना अनावश्यक होता जिस तरह उच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया है, और इस प्रकार पास अपीलकर्ता के खिलाफ कर दे जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए जाये।

वह परिस्थिति यह है कि सहायक सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के बयान के उस हिस्से को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया था जिसमें उसने कहा था कि वह वह स्थान दिखाएगा जहां उसने गहने छिपाए थे और इस पर भरोसा करते हुए उसने माना कि अपीलकर्ता के पास ये सत्रह आभूषण थे, जो उसने बगीचे से खोदकर निकाले थे, जो दूसरों के साथ उसके स्वामित्व में था। हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता के बयान का वह हिस्सा जहां उसने कहा था कि उसने गहने छिपाए थे, साक्ष्य में अस्वीकार्य है। यही बात दूसरे आरोपी के खिलाफ मामले पर भी लागू होती है, 'जिसने कहा था कि उसने बड़ा साब को एक आभूषण दिया था और वह उससे इसे बरामद करवा देगा। हालाँकि सत्र न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी के बयान के उस हिस्से को विशेष रूप से खारिज नहीं किया है जहाँ उन्होंने कहा था कि उन्होंने बड़ा साब को आभूषण दिए थे, उन्होंने अपीलकर्ता के संबंध में जो कहा था, अन्य आरोपी के इस बयान को लगातार महत्व नहीं दिया। इसलिए यदि अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों के बयान का यह हिस्सा जिसके कारण आभूषणों की खोज हुई, स्वीकार्य है, तो यह माना जाना चाहिए कि अपील अदालत ने उन साक्ष्यों को गलत तरीके से खारिज कर दिया जो स्वीकार्य थे। इन परिस्थितियों में, मामला स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों द्वारा कवर किया जाएगा जो हमने ऊपर निर्धारित किए हैं, क्योंकि प्रासंगिक साक्ष्य को अस्वीकार्य के रूप में खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित होगा ताकि उन साक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद जिन्हें गलत तरीके से अस्वीकार्य करार दिया गया था, साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जा सके। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय को मामले के इस पहलू के बारे में पता था, क्योंकि फैसले के एक हिस्से वह कहता है कि एकमात्र संभावित निष्कर्ष जो निकाला जा सकता था वह यह था कि उस गुप्त जगह में रखे जाने से पहले अपीलकर्ता के पास चोरी का माल था। जैसा कि अपीलकर्ता ने अपने बयान में स्वीकार किया है, जिसका एक हिस्सा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। यदि उच्च न्यायालय ने खुद को केवल बयान के इस भाग की स्वीकार्यता तक ही सीमित रखा होता, तो बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित होता। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय आगे बढ़ गया और उन सबूतों का भी मूल्यांकन किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जैसा कि लोर्गेद्रेनाथ के मामले में इस न्यायालय ने माना था। हालाँकि, यदि स्वीकार्य साक्ष्य को खारिज कर दिया गया और उस पर विचार नहीं किया गया, तो हमारी राय में यह पुनरीक्षण में बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का एक आधार होगा।

आइए फिर हम इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या अपीलकर्ता का यह कथन कि उसने उन्हें (आभूषणों को) छिपाया था" और "वह स्थान बताएगा" जहां वे थे, धारा 27 के तहत साक्ष्य में पूरी तरह से स्वीकार्य है या केवल इसका वह हिस्सा स्वीकार्य है जहां उसने कहा था कि वह जगह बताएगा लेकिन वह हिस्सा नहीं, जहां उसने कहा था कि उसने गहने छिपाए थे। इस संबंध में सत्र न्यायाधीश ने पुलुकुरी कोटाय्या बनाम राजा-सम्राट (1946-एल.आर. 74 आ.ईए.65) पर भरोसा किया जहां एक हत्या के मामले में चाकू की बरामदगी के बयान के एक हिस्से को न्यायिक समिति द्वारा अस्वीकार्य माना गया था। उस मामले में न्यायिक समिति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर विचार किया, जो इन शर्तों में है:-

"बशर्ते, जब कोई तथ्य किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजा गया हो, तो ऐसी बहुत सी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से संबंधित है, को साबित किया जा सकता है।"

यह अनुभाग धाराओं 25 और 26 का अपवाद है, जो किसी पुलिस अधिकारी के सामने किए गए कबूलनामे या किसी व्यक्ति के पुलिस हिरासत में रहने के दौरान किए गए कबूलनामे के सबूत पर रोक लगाते हैं, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न की गई हो। धारा 27 अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के उस हिस्से की अनुमति देती है "चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं" जो उस तथ्य से विशिष्ट रूप से संबंधित है जिसके द्वारा साबित किया जाना पाया गया है।

इस प्रकार पुलिस के समक्ष एक इकबालिया बयान भी, जो स्पष्ट रूप से किसी तथ्य की खोज से संबंधित है, धारा 87 के तहत साबित किया जा सकता है। उस मामले में न्यायिक समिति को इस बात पर विचार करना था कि आरोपी द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी में से कितनी जानकारी धारा 17 के तहत स्वीकार्य होगी, और उस संबंध में "इतनी सारी जानकारी जो उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो" शब्दों पर जोर दिया। यह माना गया कि स्वीकार्य जानकारी की सीमा खोजी गई जानकारी की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का संबंध होना आवश्यक है। आगे यह बताया गया कि "खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु को प्राप्त गया है और इसके बारे में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।" आगे यह भी देखा गया-

"पिछले उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी, या बताई गई वस्तु का पिछला इतिहास उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है।"

इसका उदाहरण न्यायिक समिति ने यह कहकर दिया-

"हिरासत में एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि 'मैं अपने घर की छत में छिपा हुआ एक चाकू पेश करूंगा' से इस तथ्य का पता चलता है कि मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार एक चाकू छिपा हुआ है, और यदि चाकू का इस्तेमाल अपराध कारित करने में साबित हो गया तो खोजा गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। हालांकि, बयान में इन शब्दों को जोड़ा जाए 'जिससे मैंने 'ए' पर वार किया था', तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे मुखबिर के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।"

यदि हम सम्मानपूर्वक ऐसा कह सकें, तो यह मामला स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि कथन का कौन सा भाग धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। यह केवल वह भाग है जो स्पष्ट रूप से खोज से संबंधित है जो स्वीकार्य है; लेकिन अगर बयान का कोई हिस्सा स्पष्ट रूप से खोज से संबंधित है तो यह पूरी तरह से स्वीकार्य होगा और अदालत यह नहीं कह सकती कि वह बयान के एक हिस्से को हटा देगी क्योंकि यह इकबालिया प्रकृति का है। धारा 27 बयान के उस हिस्से को समग्र रूप से स्वीकार्य बनाती है जो स्पष्ट रूप से खोज से संबंधित है, चाहे वह स्वीकारोक्ति की प्रकृति में हो या नहीं। अब इस मामले में बयान में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने कहा कि वह वह जगह दिखाएगा जहां उसने गहने छिपाए थे। सत्र न्यायाधीश ने इस कथन के उस भाग को, जिसका आशय यह है कि 'जहां उसने उन्हें छिपाया था' स्वीकार्य नहीं माना है। यह स्पष्ट है कि यदि कथन के उस भाग को हटा दिया जाए तो शेष कथन (अर्थात् वह वह स्थान दिखा देगा) पूरी तरह से निरर्थक होगा। हमारी राय में यह पूरा कथन स्पष्ट रूप से आभूषणों की खोज से संबंधित है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। न्यायिक समिति के फैसले में दिए गए उदाहरण में "जहां उसने उन्हें छिपाया था" शब्द "जिससे मैंने मृतक को चाकू मारा" के बराबर नहीं हैं। इन शब्दों

(अर्थात्, जहां उसने उन्हें छिपाया था) का अपराध के पिछले इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है और स्पष्ट रूप से वास्तविक खोज से संबंधित है जो उस कथन के आधार पर हुई। हालाँकि यह आग्रह किया जाता है कि ऐसे मामले में जहां अपराध में कब्ज़ा शामिल है, यह शब्द भी कि "जहां उसने उन्हें छिपाया था" भी अस्वीकार्य होंगे क्योंकि वे आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति के समान होंगे कि उसका कब्ज़ा था। हमारी राय में इस तर्क के दो उत्तर हैं। पहली जगह में, धारा 27 स्वयं कहती है कि जहां बयान स्पष्ट रूप से खोज से संबंधित है, यह स्वीकार्य होगी चाहे यह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं। दूसरे स्थान पर, ये शब्द अपने आप में भले ही अपीलकर्ताओं के कब्जे को दिखाते हों, लेकिन अपराध को साबित नहीं करेंगे, क्योंकि सामान बरामद होने के बाद, अभियोजन पक्ष को अभी भी यह दिखाना होगा कि बरामद सामान अपराध से जुड़े हैं, यानी इसमें मामले में, अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि वे चोरी की संपत्ति हैं। इसलिए हमारी राय है कि अपीलकर्ता के साथ-साथ दूसरे अभियुक्त का पूरा बयान, जिसने कहा था कि उन्होंने बड़ा साब को आभूषण दिया था और उससे इसे बरामद करवा देगा) साक्ष्य के लिए स्वीकार्य होगा और सत्र न्यायाधीश इसके एक हिस्से को खारिज करने में गलत था। इसलिए, चूंकि प्रासंगिक और स्वीकार्य साक्ष्य सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, यह बिल्कुल उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के निष्कर्ष को रद्द करने का हकदार होगा, हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने खुद को केवल इस बिंदु तक ही सीमित नहीं रखा और बल्कि साक्ष्य के अन्य भागों के बारे में मजबूत टिप्पणियाँ की।

अगला सवाल यह है कि वर्तमान जैसे मामले में क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर भी विचार किया। ऐसे मामले में दो आकस्मिकताएँ उत्पन्न होती हैं। एक तो यह कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किया जा सकता है। ऐसे मामले में यदि उच्च न्यायालय, ऊपर बताए गए सिद्धांतों के आधार

पर, पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित समझता है, तो उसके पास एकमात्र रास्ता दोषमुक्ति को रद्द करना और मामले को पुनः विचारण के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेजना है। लेकिन एक अन्य प्रकार का मामला भी हो सकता है, अर्थात्, जहां विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है जबकि अपील अदालत ने उसे बरी कर दिया है। ऐसे मामले में यदि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अपील अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो सवाल यह है कि क्या अपील अदालत को उस बयान को स्वीकार करने के बाद अपील पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया जाना चाहिए जिसे उसने खारिज कर दिया था या क्या आवश्यक रूप से पुनः विचारण होना चाहिए। जहां तक इसका संबंध है, हमारी राय है कि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह दोनों में से कोई भी एक रास्ता अपनाए। यह पुनः विचारण का आदेश दे सकता है या अपील अदालत को अपील पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दे सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या उच्च न्यायालय अपील अदालत को अपील पर फिर से सुनवाई करने का आदेश देगा या विचारण न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई का आदेश देगा। जहां, इस मामले में, पूरे सबूत मौजूद हैं और यह अपील अदालत थी जिसने विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए सबूतों को खारिज कर दिया था, हमारी राय में उचित कदम अपील को अपील अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेजना है। ऐसे मामले में विचारण न्यायालय का आदेश दोबारा सुनवाई पर अपील अदालत के फैसले के अधीन रहेगा। वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि पूरे साक्ष्य पेश किए गए हैं और एकमात्र दोष यह है कि अपील अदालत ने उन साक्ष्यों को गलत तरीके से खारिज कर दिया, जिन्हें विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि उचित कदम यह है कि अपील अदालत को अपील पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए और या तो उन सबूतों जिन्हें उसने पहले खारिज कर दिया था पर विचार करने के

बाद दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाए या आरोपी को बरी कर दिया जाए यदि ऐसा कदम लेना न्यायोचित है। हमें यह जोड़ना चाहते हैं कि अपील अदालत जब अपील पर दोबारा सुनवाई करे तो उसे साक्ष्यों पर उच्च न्यायालय की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और साक्ष्यों के उस हिस्से पर विचार करने के बाद जो इसके द्वारा पहले अस्वीकार्य माने गए थे, उसे अपने खुद के विवेक का उपयोग करना चाहिए।

इसके बाद दूसरे आरोपी का मामला रह जाता है। हमारी राय है कि चूंकि हम अपील अदालत को अपीलकर्ता के संबंध में अपील को फिर से सुनने का निर्देश दे रहे हैं, इसलिए यह उचित है कि दूसरे आरोपी से संबंधित आदेश को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसकी अपील पर भी ऊपर बताए गए तरीके से, फिर से सुनवाई की जानी चाहिए। इसलिए हम दूसरे आरोपी पर दोबारा मुकदमा चलाने के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि उसकी अपील पर भी अपीलकर्ता की अपील के साथ फिर से सुनवाई की जाएगी।

अपील को अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।